

उन्मुक्त द्वार की नीति [Open door policy]

Ashish Kumar Thakur
B.A. II, History (H), paper-12
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur.

- चीन और अमेरिका :-

चीन में यूरोपीय राज्यों की छीना-झपटी देखकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चिन्तित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। पश्चिम देशों में यदि चीन का किसी राज्य से जोड़ा बहुत अच्छा संबंध था तो अमेरिका ही था। 1884 ई० में निरन्तर उसने चीन के व्यापार के विकास में सहायता की थी। अमेरिका ने चीन के साथ कुछ नहीं किया था। लेकिन अमेरिका अधिक दिनों तक इस संबंध की नीति से काम नहीं चला सका। 1898 ई० में उसने स्पेन को हराकर फिलिपाइन्स पर अधिकार कर लिया था। इस हालत में पूर्वी एशिया की राजनीतिक गतिविधि में उसकी रुचि का बढ़ना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त अमेरिका एक महान औद्योगिक देश बन गया था। और उसे बाहर बाजारों की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में वह चीन की धूर-खुस्तोत को छुप-चाप नहीं देख सकता था। जब फ्रांस ने क्वांग्सी पर, जापान ने फुकियुन पर, ब्रिटेन ने ग्रांग्सी घाटी पर और रूस ने मंचूरिया पर अधिकार जमा रखा था। इस चर्चने से इस बात से सम्भावना बढ़ गई थी कि उपर्युक्त कौड़े देश अपने-अपने अधिकृत देश/प्रदेश में ऐसी शत्रुतापूर्ण चुँबी व्यवस्था रखते जिसमें अमेरिका के लिए चीन में व्यापार करना कठिन हो जाय। उपर अमेरिका चीन में अपना प्रभाव क्षेत्र भी नहीं कायम कर सकता था।

फिलिपाइन्स कीप समूह पर जब अमेरिका ने अधिकार किया तो इसके कुछ हलकों में इसका तीव्र विरोध हुआ था। कुछ अमेरिकियों ने इसे बाजारज्य की मौलिक नीति के विरुद्ध बताया। अतः स्पष्ट था कि यदि अमेरिका चीन में अपना उपनिवेश कायम करने का प्रयास करता तो अमेरिका में उनका विरोध होता।

जॉन हे द्वारा उन्मुक्त द्वार नीति का प्रतिपादन :-

1898 ई० में जॉन हे संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेश सचिव नियुक्त हुआ। चीन में अमेरिका हितों की रक्षा के लिए उसने एक नई नीति का प्रतिपादन किया, जिसे 'उन्मुक्त द्वार की नीति' कहते हैं। 6 अप्रैल 1899 को उसने ब्रिटेन, जर्मनी और रूस की सरकारों का एक शहती पत्र भेजा और नवम्बर में जापान, इटली तथा फ्रांस की सरकारों को लिखा और उसने यह घोषणा करने की माँग की कि चीन में सभी देशों को व्यापार करने की समान सुविधाएँ दी जाएँ, सभी से समान सीमा शुल्क और वंपरगाह का फिशा लिया जाय और इन संबंध में किसी एक देश के साथ दूसरे की अपेक्षा रियासत नहीं किया जाय। और चीन के सीमा शुल्क में चीन को भी हिस्सा दिया जाय।

Ashish

और चीनी सरकार का चुंबी वस्तुल करने का अधिकार
असुल्य रहे। दुसरे शब्दों में, सचिव हैं ने उन देशों से जो चीन
की हानी पर चढ़ बैठें हैं, यह घोषणा करने को कहा कि चीन के
साथ मुक्त व्यापार की नीति' वरती जाय। और सभी देशों के
समान रूप से सीमा शुल्क और चुंबी वस्तुल की जाय।

इस शर्ती पत्र में कहा गया था कि " हमारी सरकार
उप्य से यह चाहती है कि अमेरिका के नागरिकों के साथ
चीन में उन देशों के द्वारा जिन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र कायम
कर लिया है और जिनका चीन के कुछ भागों पर अधिकार
हो गया है, ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार ना ही जिससे हमारे
नागरिकों को शिकायत का मौका मिले। हमारी सरकार यह
भी चाहती है कि चीन में दूसरों के सत्त्विक देश को
व्यापार करने की समान सुविधाएँ हों। हम चाहते हैं कि
ऐसे सभी अवसरों को दुरुस्त हवा दिया जाय, जिससे
अंतराष्ट्रीय कदम उत्पन्न हो सकनी हैं।"

20 मार्च 1900 को जॉन हे ने यह घोषणा
की उसे " सभी देशों से सलोचजनक आश्वासन मिले हैं।"
इस राजनायिक इनासे में और कोई विदेशी राष्ट्र में नही
आया, लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी और मुक्ति-आंदोलन के
समर्थक लोग अवश्य बोस्ये में आ गए। यह घोषणा बन
गई कि अमेरिका एक उपनिवेशवाद-विरोधी देश है तथा
उसने अपने राजनायिक प्रतिभा से चीन को लुटेरे देशों
के कुलित देशों से बचा लिया। कुछ लोग वसत मुलावे में
अवश्य आ गया कि अमेरिका का उदेश्य चीनी साम्राज्य को
डुफड़े-डुफड़े होने से बचाना था।

तब में यह है कि इसमें कोई ऐसी बात नही था
इसमें तनिक भी संदेह नही करना चाहिये कि मूल रूप से एक
साम्राज्यवादी देश होने के नाते अमेरिका द्वारा इस विद्वान
का प्रतिपादन अपने लाभ को दृष्टि में रख कर किया गया था
और इस मांग के पीछे चीन में अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र
बनाने की इच्छा थी।

चीन का विपतन नही हुआ था किनो चीन की कुछ रक्षा ही
सकी तो वह अमेरिका की रुपा से नही, बल्कि
यूरोपीय देशों की अपनी खींचतानी के कारण।

Feb 1900